न्यायमूर्ति एम. आर. अग्निहोत्री के समक्ष

सुंदर शाम कपूर और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

माननीय मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ और अन्य,-प्रतिवादी

सिविल रिट याचिका संख्या 2363, 1985, 6 अगस्त, 1987

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 229, 231 और 309-मुख्य न्यायाधीश की नियम बनाने की शक्ति-उस शक्ति का विस्तार-वित्तीय निहितार्थ वाले नियम-ऐसे नियमों की मंजूरी-नियमों के प्रकाशन की आवश्यकता-प्रकाशन की तिथि-क्या नियमों का प्रवर्तन ऐसी तारीख से ।

माना गया कि मुख्य न्यायाधीश राज्य में न्यायपालिका का प्रमुख होता है और उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश या उसका नामित व्यक्ति सर्वोच्च प्राधिकारी होता है। मुख्य न्यायाधीश के पास न केवल नियुक्तियों के मामले में बल्कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने के संबंध में भी विशेष शक्ति है। नियमों के मामले में राज्यपाल की मंजूरी केवल वेतन, भत्ते, छुट्टी या पेंशन से संबंधित नियमों तक ही सीमित है। सेवा शर्तों के संबंध में अन्य सभी नियमों के लिए उनकी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

(पैरा 10).

यह अभिनिर्णीत किया गया है कि भले ही मसौदा नियमों को 18 मार्च, 1974 को मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया गया था और 1 मार्च, 1974 से उनके प्रवर्तन के आदेश पारित किए गए थे, फिर भी तथ्य यह है कि इन नियमों को न तो सूचित किया गया था। नियमों को उनके अंतिम रूप में औपचारिक रूप से अधिनियमित किया गया था, न ही उन्हें 23 जनवरी, 1975 तक प्रकाशित किया गया था। इसलिए, यह निर्णायक रूप से नहीं माना जा सकता है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा 1 मार्च, 1974 से लागू करने का आदेश दिया गया नियम वास्तव में लागू हुआ

था। उसी तारीख को बल लागू किया गया, हालाँकि उन्हें औपचारिक रूप से 23 जनवरी, 1975 को अधिसूचित किया गया था। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि कुछ नियमों में निहित वैधानिक प्रावधानों का ईमानदारी से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि उन नियमों को प्रख्यापित किया जाना चाहिए, यदि औपचारिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया.

(पैरा 11).

यह अभिनिर्णीत किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने नियमों को मंजूरी देते समय विशेष रूप से प्रावधान किया था कि "ये नियम उनके जारी होने की तारीख से लागू होंगे"। इसलिए, एकमात्र अनूठा निष्कर्ष जिस पर पहुंचा जा सकता है, वह यह है कि जो नियम मुख्य न्यायाधीश द्वारा 23 जनवरी, 1975 की अधिसूचना के साथ जारी किए गए थे, उन्हें इस निर्देश के साथ भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ था कि "ये नियम लागू होंगे।" उनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे", कानून की नजर में 23 जनवरी, 1975 से ही लागू होंगे, किसी अन्य तारीख से नहीं।

(पैरा 15)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय इस पर कृपा करें: -

(i) जारी नियम निसी;

(ii) अभिलेखों को मंगाना और उनका अवलोकन करना;

(iii) अनुलग्नक पी.5 को रद्द/अलग करते हुए, सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट जारी करें, जो भेदभावपूर्ण है, कर्मचारियों के हितों के लिए हानिकारक है और प्रतिवादी संख्या 2 के अनुमोदन का उल्लंघन है और प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है।

(iv) कोई अन्य उचित रिट, आदेश और/या निर्देश जारी करें जो माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे;

(v) निषेध, परमादेश और किसी अन्य आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी करें, जिसमें उत्तरदाताओं को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (नियुक्ति स्थापना और सेवा की शर्तें) नियम 1973 को उनके जारी होने की तारीख से प्रभावी करने का निर्देश दिया जाए। 1 मार्च, 1974 न कि

भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन का संचार पत्र जारी होने की तारीख से, यानी 25 सितंबर, 1985 से; और याचिकाकर्ताओं को समय-समय पर अर्जित सभी परिणामी लाभों के साथ 1 मार्च, 1974 से 25 सितंबर, 1985 तक वेतन और भत्तों के अंतर और बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया गया;

(vi) अनुलग्नक पी. 1 से पी. 5 की प्रमाणित/मूल प्रतियां दाखिल करने से छूट।

(vii) उत्तरदाताओं को पूर्व नोटिस देने की आवश्यकता को हटा दें। समय की कमी और मामले की तात्कालिकता को देखते हुए और

(viii) याचिकाकर्ताओं को लागत के पक्ष में आदेश ।

याचिकाकर्ताओं की ओर से के.टी.एस. तुलसी, वकील और के.एस. डडवाल, वकील।

प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से वकील जी. सी. गर्ग।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से एच. एस. बराड़, वकील।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से यू.टी. चंडीगढ़ के वरिष्ठ स्थायी वकील अशोक भान, वकील ए.के.मितल के साथ।

निर्णय

न्यायमूर्ति एम. आर. अग्निहोत्री

(1) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना पर कार्यरत उनतीस कर्मचारियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है, जिसमें इस न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए बुलाया गया है कि क्या उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम - जिसे इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है, भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 231 के साथ पठित अनुच्छेद 229

के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियां, उच्च न्यायालय से जुड़े कर्मचारियों पर सेवारत व्यक्तियों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और आचरण को विनियमित करती हैं, जो इस प्रभाव से लागू हुईं-

(i) 1 मार्च, 1974 - प्रशासनिक पक्ष पर नियमों के मसौदे को मंजूरी देते समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा सहमत प्रवर्तन की तारीख, या

(ii) 23 जनवरी, 1975 - जब ये नियम वास्तव में बनाए गए और पहली बार चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र में प्रकाशित हुए, - अधिसूचना संख्या 38.ई.आई./वी.जेड.27, दिनांक 23 जनवरी, 1975, या

(iii) 25 सितंबर, 1985, जब इन नियमों को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई कि "ये नियम उनके जारी होने की तारीख से लागू होंगे"

(2) याचिकाकर्ता, जो अनुवादक के रूप में काम कर रहे थे, अपने वेतनमान में संशोधन के लिए उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि उनके मौजूदा वेतनमान उनकी शैक्षणिक योग्यता और उनके द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति के अनुरूप नहीं थे। उनकी शिकायतों की वास्तविकता से संतुष्ट महसूस करते हुए, उच्च न्यायालय ने, अपने प्रशासनिक पक्ष से, उनके वेतनमान में संशोधन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन, प्रतिवादी नंबर 3 को उनके मामले की सिफारिश की, - बीस साल से अधिक पहले भेजे गए एक संचार के माध्यम से। जबकि मामला अभी भी विचाराधीन था और पत्राचार चल रहा था, पंजाब वेतन आयोग ने राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले जूनियर/सीनियर अनुवादकों के वेतनमान में संशोधन की सिफारिश की। उच्च न्यायालय प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के मामले में पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नियमों का निर्धारण स्वयं उच्च न्यायालय के विचाराधीन था, निम्नलिखित 15 अप्रैल, 1971 को मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रशासनिक पक्ष पर आदेश दर्ज किया गया:-

'वेतन आयोग की रिपोर्ट को टुकड़ों में लागू नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम पंजाब वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आलोक में

बनाए जा रहे हैं। इसलिए, अनुवाद शाखा के लिए पुनरीक्षक के रूप में काम करने के लिए उप अधीक्षकों के 6 पदों के सृजन के कार्यालय के प्रस्ताव को फिलहाल अस्वीकार किया जा सकता है। जो नए नियम बनाए जा रहे हैं, उनके मुताबिक जरूरत पड़ने पर पद सृजित किए जाएंगे।'

(3) इसके तुरंत बाद, नए नियमों को तैयार करने का कार्य शुरू किया गया और नियमों का मसौदा, जैसा कि तैयार किया गया था, 18 मार्च, 1974 को मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिसमें नियमों को 1 तारीख से लागू करने का प्रस्ताव था। मार्च, 1974। इस प्रस्ताव पर 18 मार्च, 1974 को ही तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने सहमति दे दी थी, जो कि अनुबंध पी. 1 से नीचे दिए गए प्रासंगिक उद्धरण से स्पष्ट होगाः -

"...यदि अनुमोदित हो, तो इन नियमों को 1 मार्च, 1974 से लागू और प्रभावी बनाया जा सकता है।

वित्तीय निहितार्थों से जुडे नियमों को, यदि अनुमोदित किया जाता है, तो अनुमोदन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है।

1 मार्च, 1974 के बाद की गई सभी नई नियुक्तियाँ नए नियमों द्वारा विनियमित की गई हैं।

एसडी/- . . .,

एस. डी. बजाज 18 मार्च, 1974।

माननीय मुख्य न्यायाधीश

एसडी/- . . .,

हरबंस सिंह मुख्य न्यायाधीश

18 मार्च, 1974.

इसके तुरंत बाद, इन नियमों को उच्च न्यायालय प्रतिष्ठान के सदस्यों के बीच प्रसारित किया गया ताकि उन्हें नियमों से अवगत कराया जा सके और उनका अनुपालन तुरंत सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार, ये नियम 1 मार्च, 1974 से उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने लगे।

(4) इन सबके बावजूद, तथ्य यह है कि शक्ति के स्रोत और अधिनियमित करने के अधिकार के औपचारिक उद्धरण के साथ नियमों को अधिनियमित करने के संबंध में औपचारिक अधिसूचना 23 जनवरी, 1975 तक जारी नहीं की गई थी। जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी, 1975, जिसे पहले ही संदर्भित किया जा चुका है, को चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र दिनांक 1 फरवरी, 1975 में प्रकाशित किया गया था। जिस अधिकार के साथ उपरोक्त नियमों को अधिसूचित किया गया था उसका उद्धरण इस प्रकार है: -

"23 जनवरी, 1975. संख्या 38.ई.आई./वी.जेड.27.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 231 के साथ पठित अनुच्छेद 229 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और हरियाणा, जहां तक नियम वेतन, भत्ते, छुट्टी या पेंशन से संबंधित हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ, उच्च न्यायालय से जुड़े कर्मचारियों पर सेवारत व्यक्तियों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और आचरण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है। "

(5) यद्यपि उपरोक्त नियमों को विधिवत अधिसूचित किया गया था और उच्च न्यायालय में कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और आचरण को विनियमित करने के लिए उन पर कार्य किया जा रहा था और उनका सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा था, फिर भी नियमों को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी, विशेष रूप से भारत सरकार को बार-बार अनुस्मारक जारी करने के बावजूद नियम 26, 27 और 34 और अनुसूची I, 1(ए) और III की जानकारी मुख्य न्यायाधीश को नहीं दी गई। पूरे दस साल बीत चुके थे, फिर भी भारत के राष्ट्रपति की अपेक्षित मंजूरी अभी भी प्रतीक्षित थी, भले ही यह विशेष रूप से भारत सरकार के ध्यान में लाया गया था कि सेवा नियम पहले ही 1 मार्च से पहले ही अधिनियमित और लागू किए जा चुके थे। , 1974. अंततः, 25 सितंबर, 1985 को भारत सरकार द्वारा एक पत्र भेजा गया (अनुलग्नक पी-4) जिसमें भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी इस निर्देश के साथ दी गई थी कि "ये नियम उनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।"

(6) यद्यपि उपरोक्त नियम 23 जनवरी 1975 को पहले ही जारी किये जा चुके थे; जैसा कि चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र दिनांक 1 फरवरी, 1975 में प्रकाशित हुआ था, और मामले को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ अंतिम रूप दिया गया, 25 सितंबर, 1985 को सूचित किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि ये नियम उनके जारी होने की तारीख से लागू होंगे, फिर भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर उच्च न्यायालय ने अपने प्रशासनिक पक्ष से 23 जनवरी, 1986 (अनुलग्नक पी. 5) को एक नई अधिसूचना जारी की, जिसमें संकेत दिया गया कि नियम 25 सितंबर, 1985 से प्रभावी होंगे; स्पष्ट रूप से इसका मतलब यह है कि वे 1 मार्च, 1974 से या किसी भी मामले में 23 जनवरी, 1975 से कभी भी लागू नहीं हुए, जो कि प्रशासनिक पक्ष पर उच्च न्यायालय का रुख था।

(7) 23 जनवरी, 1986 (अनुलग्नक पी. 5) की अधिसूचना जारी होने से व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने इसे रद्द करने और प्रतिवादियों को 1 मार्च मानने का आदेश देते हुए परमादेश की रिट जारी करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। , 1974, नियमों को जारी करने की तारीख के रूप में और उसके आधार पर अन्य परिणामी राहतों के साथ वेतन और भत्तों की बकाया राशि जारी करने के लिए।

(8) रिट याचिका के जवाब में, हालांकि अलग-अलग रिटर्न दाखिल किए गए हैं, एक श्री एन.एस. राव, रजिस्ट्रार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा, मुख्य न्यायाधीश, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से, और दूसरा श्री सुरेंद्र सिंह द्वारा। , भारत सरकार के उप सचिव, कानून और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली, भारत संघ की ओर से, प्रतिवादी संख्या 2, फिर भी लिया गया रुख लगभग समान है; अर्थात्, भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी 25 सितंबर, 1985 को सूचित कर दी गई है, नियम उनके जारी होने की तारीख से लागू होंगे। हालाँकि, भारत संघ ने एक और रुख अपनाया है कि राष्ट्रपति की मंजूरी को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है और इसलिए, नियम केवल उस तारीख से लागू होंगे जिस दिन राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई थी। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने केवल यह कहकर सामग्री को आराम दिया है कि, "उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने 23 जनवरी, 1975

से इन नियमों का लाभ बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ मामला उठाया है। सरकार का जवाब इस संबंध में भारत की ओर से अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है और इस प्रकार रिट याचिका अपरिपक्व है और केवल इस आधार पर खारिज करने योग्य है।

(9) भारत के संविधान ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में सेवारत कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों और अधिकारियों को अधिकृत करने के लिए अलग-अलग प्रावधान किए हैं: जिस तरह अनुच्छेद 309 किसी राज्य के राष्ट्रपति या राज्यपाल को नियम बनाने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। संघ या राज्य के अधीन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, जैसा भी मामला हो, संविधान के अनुच्छेद 229 का खंड (2) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अधिकारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है। और इस संबंध में नियम बनाकर उच्च न्यायालय के सेवक। अनुच्छेद 229 के खंड (2) के साथ-साथ अनुच्छेद 309 को इस प्रकार पढ़ें: -

“229. (2) राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कुछ अन्य द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। इस उद्देश्य के लिए नियम बनाने के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिकृत न्यायालय के अन्य न्यायाधीश या अधिकारी:

बशर्ते कि इस खंड के तहत बनाए गए नियमों के लिए, जहां तक वे वेतन, भत्ते, छुट्टी या पेंशन से संबंधित हैं, राज्य के राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

309. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें - इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, उपयुक्त विधानमंडल के अधिनियम सार्वजनिक सेवाओं और संबंधित पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकते हैं। संघ या किसी राज्य के साथ:

बशर्ते कि यह राष्ट्रपति या ऐसे व्यक्ति के लिए सक्षम होगा जिसे वह संघ के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों के मामले में निर्देशित कर सकता है, और किसी राज्य के राज्यपाल या ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे वह निर्देशित कर सकता है। राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों के लिए, ऐसी सेवाओं और पदों पर भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाना, जब तक कि इसके तहत उपयुक्त विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रावधान नहीं किया जाता है। अनुच्छेद, और इस प्रकार बनाए गए कोई भी नियम ऐसे किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रभावी होंगे।"

(10) अनुच्छेद 229 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त मुख्य न्यायाधीश की नियम बनाने की शक्ति का दायरा और किस हद तक इस शक्ति को इस खंड के परंतुक में परिकल्पित अनुमोदन के अधीन बनाया गया है, विषय वस्तु रही है पिछले दो दशकों के दौरान सर्वोच्च न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में उनके आधिपत्य द्वारा कई निर्णय लिए गए। इस संबंध में, निम्नलिखित का संदर्भ दिया जा सकता है: एम. गुरुमूर्ति बनाम महालेखाकार, असम और नागालैंड और अन्य, असम राज्य बनाम भुभन चंद्र दत्त और अन्य, आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम टी. गोपालकृष्णन मूर्ति और अन्य, कुलकर्णी वी.के. बनाम महालेखाकार और अन्य, आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य बनाम एल.वी.ए. दीक्षितुलु और अन्य आदि, और एच. एल. विज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। संक्षेप में, उनका आधिपत्य इस प्रकार है: -

(i) अनुच्छेद 229 को लागू करने में संविधान निर्माताओं का स्पष्ट उद्देश्य और स्पष्ट इरादा यह है कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति के मामले में, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को सर्वोच्च प्राधिकारी होना चाहिए। और अनुच्छेद में प्रदान की गई सीमित सीमा को छोड़कर कार्यपालिका द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यह अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता को सुरक्षित और बनाए रखने के लिए है।

(ii) अनुच्छेद 229 के खंड (2) के साथ पढ़ा जाने वाला खंड (1) न केवल नियुक्तियों के मामले में बल्कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने के संबंध में भी विशेष शक्ति प्रदान करता है।

(iii) नियमों के मामले में राज्यपाल की मंजूरी केवल वेतन, भत्ते, छुट्टी या पेंशन से संबंधित नियमों तक ही सीमित है। सेवा शर्तों के संबंध में अन्य सभी नियमों के लिए उनकी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

(iv) अनुच्छेद 229 में एक विशिष्ट और अलग योजना है और उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों के मामले में मुख्य न्यायाधीश को पूर्ण स्वतंत्रता पर विचार करता है जो उनके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

(v) जब किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सिफारिशें मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती हैं, तो यह चीजों की उपयुक्तता और अनुच्छेद 229 की भावना के अनुरूप होगा कि आम तौर पर और आम तौर पर उक्त सिफारिशें होनी चाहिए राज्यपाल/राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब यह स्वीकार किया जाता है कि लोगों की संप्रभुता तीन अंगों- कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में परिलक्षित होती है। मुख्य न्यायाधीश किसी राज्य में न्यायपालिका का प्रमुख होता है। इसलिए, जब वह सिफारिशें करते हैं तो अपरिहार्य धारणा यह होती है कि वे पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ और विभिन्न सार्वजनिक हितों के साथ-साथ वित्तीय पहलुओं पर विचार करने के बाद बनाई गई हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 229 के खंड (2) के तहत मुख्य न्यायाधीश को प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति का दायरा और सीमा है, जब 18 मार्च, 1974 को मुख्य न्यायाधीश ने नियमों के मसौदे को मंजूरी दी और प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। प्रशासनिक पक्ष, कि नियमों को 1 मार्च, 1974 से लागू और प्रभावी बनाया जा सकता है, प्रथम दृष्टया नियमों के अधिनियमन और प्रवर्तन को पूरा करने के लिए कोई अन्य औपचारिकता नहीं देखी जानी बाकी है। फिर भी, वित्तीय निहितार्थों से जुड़े नियमों को, निश्चित रूप से, भारत के राष्ट्रपति को संदर्भित करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए

संदर्भ तदनुसार मुख्य न्यायाधीश (राज्यपाल के बजाय, भारत के राष्ट्रपति) द्वारा किया गया था क्योंकि उच्च न्यायालय सामान्य है पंजाब और हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़)।

(11) भले ही मसौदा नियमों को 18 मार्च, 1974 को मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया गया था, और 1 मार्च, 1974 से उनके प्रवर्तन के आदेश पारित किए गए थे, फिर भी तथ्य यह है कि इन नियमों को सूचित करते हुए न तो अधिसूचित किया गया था। नियमों को उनके अंतिम रूप में औपचारिक रूप से अधिनियमित किया गया था, न ही उन्हें 23 जनवरी, 1975 तक प्रकाशित किया गया था। इसलिए, यह निर्णायक रूप से नहीं माना जा सकता है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा 1 मार्च, 1974 से लागू करने का आदेश दिया गया नियम वास्तव में लागू हुआ था। उसी दिन बल लागू किया गया, हालाँकि उन्हें औपचारिक रूप से 23 जनवरी, 1975 को अधिसूचित किया गया था। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि कुछ नियमों में निहित वैधानिक प्रावधानों का ईमानदारी से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि उन नियमों को प्रख्यापित किया जाना चाहिए, यदि औपचारिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया. इस संबंध में, हरला बनाम राजस्थान राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है, जिसमें इसे निम्नानुसार माना गया था: -

"किसी विशेष कानून या प्रथा के अभाव में, हमारी राय है कि किसी राज्य के विषयों को उन कानूनों द्वारा दंडित या दंडित करने की अनुमति देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी।" उचित परिश्रम करने पर भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। प्राकृतिक न्याय के लिए आवश्यक है कि किसी कानून को लागू होने से पहले उसे प्रख्यापित या प्रकाशित किया जाना चाहिए। इसे कुछ पहचानने योग्य तरीके से प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि सभी लोग जान सकें कि यह क्या है, या, कम से कम, कुछ विशेष नियम या विनियम या प्रथागत चैनल होना चाहिए जिसके माध्यम से ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जा सके। उचित और उचित परिश्रम।"

सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त आधिकारिक घोषणा के सामने, यह मानना मुश्किल होगा कि मसौदा नियम, जिन्हें 18 मार्च, 1974 को मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन 1 मार्च, 1974 से लागू करने का आदेश दिया गया था, लागू हो गए। वास्तव में, उसी तिथि से बाध्य करें। इसलिए 1 मार्च, 1974 को नियम जारी करने की तारीख नहीं माना जा सकता।

(12) जाहिर है, जब 23 जनवरी 1975 को नियमों को अधिसूचित किया गया था, जिसमें अधिकार के औपचारिक उद्धरण के साथ उनकी शक्ति के स्रोत को दर्शाया गया था, मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियम उसी तारीख से लागू हुए थे। हालाँकि नियम चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र में एक सप्ताह के भीतर, यानी 1 फरवरी, 1975 को भी प्रकाशित किए गए थे, फिर भी सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, नियमों के जारी होने की तारीख, अधिसूचना की तारीख ही होगी। वही बनाए गए थे, न कि वह तारीख जिस दिन वे वास्तव में प्रकाशित हुए थे। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 का संदर्भ सहायक होगा, जिसे संविधान के अनुच्छेद 367 द्वारा संविधान की व्याख्या के लिए लागू किया गया है। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 5 के तहत, एक केंद्रीय कानून उस दिन लागू होता है जिस दिन उसे सहमति मिलती है, न कि उस दिन जब वह राजपत्र में प्रकाशित होता है। इसलिए, 23 जनवरी, 1975 को संविधान के अनुच्छेद 231 के साथ पठित अनुच्छेद 229 के तहत मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियम, उनके जारी होने की तारीख, यानी 23 जनवरी, 1975 को ही लागू हो गए, न कि उस दिन 1 फरवरी, 1975, जब इन्हें चंडीगढ़ प्रशासन के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

(13) उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, उनकी वापसी में भारत संघ द्वारा अपनाया गया रुख कानून में पूरी तरह से अस्थिर हो जाता है। भारत संघ की इस दलील में कोई दम नहीं है कि नियम केवल 25 सितंबर, 1985 को लागू हुए थे, यानी वह दिन जब भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई थी, उससे पहले नहीं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि 25 सितंबर, 1985 के पत्र (अनुलग्नक पी.

4) में, जिसके साथ भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की गई थी, नियमों में विशेष रूप से निम्नानुसार प्रावधान किया गया था: -

"ये नियम उनके जारी होने की तारीख से लागू होंगे।"

मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए और जारी किए गए नियम - 23 जनवरी, 1975 की अधिसूचना के माध्यम से, अभिव्यक्ति "उनके जारी होने की तारीख" स्पष्ट रूप से 23 जनवरी, 1975 की तारीख से संबंधित होगी, न कि किसी से। 23 जनवरी, 1975 के बाद की तारीख। इसके अलावा, भारत के राष्ट्रपति, नियमों को मंजूरी देते समय, और भारत सरकार, कानून और न्याय मंत्रालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसकी जानकारी देते समय पूरी तरह से अवगत थे बी.एस. वडेरा आदि बनाम भारत संघ और अन्य (8) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों का पूर्वव्यापी प्रभाव भी हो सकता है। अनुच्छेद 229 के खंड (2) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली नियम बनाने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने की शक्ति के अनुरूप है, तर्क की समानता पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियम हो सकते हैं पूर्वव्यापी प्रभाव भी दिया जाए। इसलिए, तर्क के तौर पर यह मानते हुए कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों को राष्ट्रपति की मंजूरी देते समय, भारत सरकार ने 25 सितंबर, 1985 को अपने पत्र में 23 जनवरी, 1975 को तारीख के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया था। जिस पर नियम लागू हो गए थे, नियमों को जारी करने की मूल तिथि, यानी 23 तारीख के अनुरूप लाने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन को पूर्वव्यापी प्रभाव देना अभी भी उसकी क्षमता में था। जनवरी, 1975.

(14) इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर, भारत संघ का भी यही इरादा था कि 23 जनवरी, 1975 को नियम लागू होने की तारीख माना जाए। भारत संघ की यह मंशा बहस के दौरान और भी स्पष्ट हो गई, जब प्रतिवादी नंबर 2 के रिकॉर्ड से पता चला कि 24/25 जुलाई, 1984 के एक पूर्व पत्र में, भारत संघ ने स्वयं माना था कि नियम 23 जनवरी, 1975 से कार्रवाई की जा रही थी। यह पत्र इस प्रकार है: -

“विषय- भारत सरकार की मंजूरी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से प्रस्ताव। नियम 26, 27 और 34 और अनुसूची I, IA, II और III को क्रमशः ड्राफ्ट-उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 1973 में।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 5125/8-आई.वी.जेड.27, दिनांक 5 मार्च, 1981 का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है। उपरोक्त प्रस्ताव को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि यह एक रिट याचिका के साथ जुड़ा हुआ है।

2. ऐसा प्रतीत होता है कि विचाराधीन प्रस्ताव चंडीगढ़ प्रशासन के माध्यम से नहीं भेजा गया है और इसलिए, प्रस्तावों पर उस प्रशासन की टिप्पणियाँ और सिफारिशें उपलब्ध नहीं हैं। चंडीगढ़ प्रशासन के लिए वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, सहित सभी पहलुओं पर प्रस्तावों की जांच करना बहुत आवश्यक है।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपना प्रस्ताव चंडीगढ़ प्रशासन के माध्यम से भेजें। ऐसा करते समय, नवीनतम निर्णय स्थिति के आधार पर मामले को अंतिम रूप देने की दृष्टि से, प्रासंगिक नियमों को 31 जुलाई, 1984 तक अद्यतन किया जा सकता है।

4. यह माना जाता है कि प्रश्नगत नियमों पर 23 जनवरी, 1975 से कार्य किया जा रहा है - कृपया पुष्टि करें।

5. चूंकि उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि मामले को छह महीने की अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, अंतिम निर्णय 15 अक्टूबर, 1984 तक लिया जाना आवश्यक है। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि 20 अगस्त तक आवश्यक कार्रवाई करें। 1984।”

यह पत्र भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के उप सचिव श्री सुरेंद्र सिंह के हस्ताक्षर से मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने के संबंध में मामले के चरण की जानकारी देते हुए उस पत्र के पैरा 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि, “यह माना जाता है कि विचाराधीन नियमों पर 23 जनवरी, 1975 से कार्रवाई की जा रही है। कृपया पुष्टि करें।” ” प्रसंगवश, दिनांक 25 सितम्बर 1985 का पत्र (अनुलग्नक पृ. 4) जिसमें राष्ट्रपति की सहमति के साथ यह

निर्देश भी दिया गया है कि "ये नियम जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे" और साथ ही लिखित भारत संघ के वक्तव्य पर भी उसी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं।

(15) इसलिए, रिकॉर्ड पर उपरोक्त सामग्री से, एकमात्र अनूठा निष्कर्ष जो पहुंचा जा सकता है, वह यह है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा 23 जनवरी, 1975 की अधिसूचना के साथ जो नियम जारी किए गए थे, उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी भारत सरकार इस निर्देश के साथ कि "ये नियम अपने जारी होने की तारीख से लागू होंगे", कानून की नजर में 23 जनवरी, 1975 से ही लागू हो गए, किसी अन्य तारीख से नहीं।

(16) उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, मेरा मानना है कि 23 जनवरी, 1986 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी. 5) को प्रकाशित करने की शायद ही कोई आवश्यकता थी। नियमों के लागू होने की तारीख को 23 जनवरी, 1975 से 25 सितंबर, 1985 तक बदलने के लिए कानून में कोई वारंट नहीं था, जैसा कि 23 जनवरी, 1986 की अधिसूचना द्वारा किया गया है। जाहिर है, नियमों में किए गए सभी संशोधनों के बीच 23 जनवरी, 1975 और 25 सितंबर, 1985 को उन संबंधित तारीखों से प्रभावी होना था, जिन पर समय-समय पर ऐसे संशोधन जारी किए गए थे। जो नियम पहले ही लागू हो चुके हैं, उनके लागू होने की तारीख को भविष्य की किसी तारीख से दोबारा लागू करने के विचार से बदलना वैधानिक नियमों को निरस्त करने जैसा है, जिसकी न तो कानून में अनुमति है और न ही इसका कोई इरादा हो सकता है।

(17) नतीजतन, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है, 23 जनवरी 1986 की विवादित अधिसूचना (अनुलग्नक पी. 5) को रद्द कर दिया जाता है और परमादेश की रिट जारी की जाती है, जिसमें प्रतिवादियों को 23 जनवरी 1975 को प्रवर्तन की तारीख मानने का आदेश दिया जाता है। उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, और उसके आधार पर, याचिकाकर्ताओं और अन्य कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्ते के बकाया के साथ-साथ अन्य परिणामी लाभ भी दिए

जाएं, जिनके वे हकदार पाए जाते हैं। नियम। चूंकि नियमों के कार्यान्वयन में पहले ही काफी लंबी अवधि की देरी हो चुकी है, इसलिए उत्तरदाताओं को आज से तीन महीने के भीतर नियमों के अनुसार आवश्यक लाभ जारी करने का निर्देश दिया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Ravleen Kaur

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh